तुम्हें अकेले ही चलना होगा क्योंकि जरूरी नहीं जो आज साथ है वो कल भी होगा।

– अज्ञात

कामकाज शुरू होने की उम्मीद

ऐसे में ज्यादातर देश कोरोना से लड़ते हुए पूरे एहतियात के साथ अपनी सामान्य आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का मन बना रहे हैं। भारत को भी देर–सबेर यह करना ही होगा क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए अपनाए गए तरीकों से यहां भारी आर्थिक दबाव पैदा हुआ है।

राधा जोशी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सुबह दस बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में जो कुछ कहा उसमें कोई नई बात नहीं थी। लोगों को इस बार कुछ अहम घोषणाओं की उम्मीद थी, जो नहीं हुईं। ठोस आश्वासन भी नहीं मिले। संभव है, आज जारी होने वाले दिशा–निर्देशों से कुछ बातें स्पष्ट हों। प्रधानमंत्री ने 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की बात कही है, जिसे लेकर लोगों ने पहले से ही मन बना रखा था।

मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक के बाद देश भर में यह संदेश चला गया था कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है। हां, प्रधानमंत्री ने एक खास बात यह जरूर कही कि 20 अप्रैल के बाद विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की जाएगी और जहां कम खतरा होगा, वहां छूट देने पर विचार किया जाएगा। यह छूट कैसी होगी, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। दरअसल मुख्यमंत्रियों वाली बैठक में उन्होंने श्जान है तो जहान है की जगह श्जान भी, जहान भीश पर ध्यान केंद्रित करने की बात कहकर थोड़ा बहुत कामकाज शुरू होने की उम्मीद जगा दी थी।

इसे उद्योग तथा कृषि समेत विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए लॉकडाउन में छूट के संकेत के तौर पर देखा गया। लेकिन पीएम के संबोधन में इसका कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला। उनका जोर इस बात पर था कि समय पर लॉकडाउन कर देने से कोविड–19 का प्रसार अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां कम हुआ। हालांकि कोरोना के फैलने की रफ्तार भारत में भी लगातार बढ़ी है और यह कब कम होगी, कैसे कम होगी, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता।

दुनिया ने भी मान लिया है कि इसके निकट भविष्य में खत्म होने की संभावना नहीं है। ऐसे में ज्यादातर देश कोरोना से लड़ते हुए पूरे एहतियात के साथ अपनी सामान्य आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का मन बना रहे हैं। भारत को भी देर–सबेर यह करना ही होगा क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए अपनाए गए तरीकों से यहां भारी आर्थिक दबाव पैदा हुआ है। समाज का एक बड़ा वर्ग रोजी–रोटी का संकट झेल रहा है। इस संकट को जल्दी सुलझाया नहीं गया तो कोरोना से लड़ाई दिनोंदिन और मुश्किल होती जाएगी। यानी भारत का संकट दोहरा है।

इंटरनैशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक लॉकडाउन के कारण भारत के असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ श्रमिक सड़क पर आ गए हैं। इन्हें तुरंत राहत तभी दी जा सकती है, जब छोटे उद्योग और कुछ सेवाएं शुरू हों। सरकार ने राशन या अन्य राहत सामग्री बांटने का जो ऐलान किया है, उसकी अपनी सीमा है। इस तरह लंबे समय तक लोगों की गृहस्थी नहीं चलाई जा सकती। खेतों में रबी की फसल कटाई के लिए तैयार है, जिसके लिए न तो मजदूर मिल रहे हैं, न ही हारवेस्टर उपलब्ध हो पा रहे हैं। सोशल डिस्टैंसिंग के साथ नियमित आर्थिक गतिविधियां कैसे शुरू हों, इसका एक खाका जल्दी सामने आना चाहिए।

बुद्धिमान मनुष्य

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। भगवदगीता के अनुसार एक बुद्धिमान मनुष्य इन बातों से परेशान नहीं होता। जीवन के भिन्न भिन्न चरणों की विभिन्न अर्थपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था के वर्ष अर्थ शिक्षा के लिए हैं वैसे ही जवानी कर्म के लिए है। नियतकालिकता निरंतरता का उत्थान करती हैय हालांकि जीवन और प्रकृति के सभी पहलुओं में इस निरंतरता का अभाव है। आत्म–नियंत्रण व अनुशासन के जरिए हम अनिश्चितता के प्रभाव को कम करके और अपने जीवन को क्रमिक करते हुए उसे एक छोर तक ले जा सकते हैं। हालांकि जीवन सामान्य नियमों का बहुत अधिक समय तक पालन नहीं करता। यह उन चीजों के साथ मुश्किल होता जाता है जिन्हें हम तंत्र की असामान्य प्रतिक्रिया कहते हैं।

संपादकीय

चुनौती में दिखा अवसर

कोरोना संकट के समय पीएम मोदी की बढ़ती ग्लोबल पहुंच और पूछ बताती है कि यह हमारे लिए एक अवसर भी है। यह अवसर इस मायने में है कि इसके जरिए हम कूटनीति के मोर्चे पर पिछले कुछ समय में उत्पन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को पीछे छोड़ सकते हैं।

पिछले साल अगस्त में जम्मू–कश्मीर को लेकर अनुच्छेद 370 पर बड़ा फैसला हुआ। इसके बाद एक के बाद एक कई ऐसे फैसले हुए जिन पर ग्लोबल बहस हुई। अनुच्छेद 370 के बाद राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फिर नागरिकता संशोधन पर बहस शुरू हुई। आलोचकों का आरोप रहा कि इनसे मोदी सरकार अपने गवर्नेंस वाले पिच से दूर होती गई। इन घरेलू बहसों के बीच भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपना पक्ष रखना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद सवाल लगातार उठते रहे। कई प्रॉपेगैंडा भी चले। इन सबके बीच भारत की चिंता बढ़ती रही। कुल मिलाकर यह वक्त उतार–चढ़ाव भरा रहा। भारत–अमेरिका के रिश्ते भी उतार–चढ़ाव भरे रहे। इसी बीच आर्थिक सुस्ती भी सामने आने लगी। आर्थिक विकास पर सवाल उठने लगे। दरअसल ग्लोबल लेवल पर ब्रैंड मोदी का असर देश के अंदर सुदूर इलाकों तक रहता है। 2019 के आम चुनावों में मोदी की अगुआई में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद हुए तमाम रिसर्च को देखें तो उनमें मोदी व बीजेपी की जीत के पीछे दुनिया भर में लोकप्रियता रखने वाले एक मजबूत नेता की उनकी छवि ने सबसे ज्यादा काम किया। अब अगर पीएम मोदी कोरोना के खिलाफ मुहिम को ग्लोबल स्तर पर अच्छे से पेश करते हैं तो निश्चित रूप से इससे भारत की भी साख बढ़ेगी और ब्रैंड मोदी भी मजबूत होगा। लेकिन इसके लिए अगले तीस दिन बेहद अहम होंगे।

भारत सहित कई देशों की साख बहुत हद तक चार बातों पर पर निर्भर करेगी। पहली बात यह कि वह अपने देश में कोरोना से किस तरह निपटता है।

सही समय पर की पहल

नरेंद्र नाथ

कोरोना संकट पूरे विश्व के सामने एक ऐसा मसला बन कर सामने आया है जिससे लगभग सभी देश एक ही तरीके से जूझ रहे हैं। लॉक डाउन के जरिए इससे निपटने की कोशिश और इस कोशिश से पैदा हो रही गंभीर दिक्कतों को संपूर्णता में देखें तो इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद आया अब तक का सबसे बड़ा संकट बेहिचक बताया जा सकता है। इस ग्लोबल क्राइसिस ने स्वाभाविक ही वैश्विक कूटनीति को भी प्रभावित किया है। इससे भारत भी अछूता नहीं रहा है और न आगे रहेगा। भारत सहित कई देशों की साख बहुत हद तक चार बातों पर पर निर्भर करेगी। पहली बात यह कि वह अपने देश में कोरोना से किस तरह निपटता है। दूसरी बात यह कि वह ऐसे संकट के दौरान दूसरे देशों को किस तरह अपने संसाधनों से मदद पहुंचाता है। तीसरा कारक होगा, बीमारी का खतरा कम होने के बाद वह आर्थिक संकट से खुद को कैसे उबारता है।

जाहिर है, जो देश इन तीनों मानकों पर मजबूत दिखेंगे, विश्व स्तर पर उनकी साख बढ़ेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पहले चरण में इन मोर्चों पर बढ़त लेने की काफी हद तक सफल कोशिश की है। अगर वैश्विक स्तर

पर कोरोना से निबटने की कोशिशों को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले यह संदेश दिया कि इस रोग से निपटने के लिए दुनिया को एक साथ आना होगा। मार्च के तीसरे हफ्ते तक तमाम दूसरे देश अलग–अलग अपनी–अपनी सीमाओं में इस रोग से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन पीएम मोदी ने सार्क देशों को एक मंच पर बुलाकर इसके लिए संयुक्त रूप से पहल करने की जरूरत बताई और एक कॉमन फंड बनाने की दिशा में भी प्रयास आगे बढ़ाए। पीएम मोदी ने यह पहल इस तथ्य के बावजूद की कि इससे पहले भारत सार्क की प्रासंगिकता पर सवाल उठा चुका था। उन्हें यह समझने में वक्त नहीं लगा कि जब सार्क की प्रासंगिकता सवालों के घेरे में थी, तब वक्त और था।

जनतकिोरोना के संकट ने अचानक हालात पूरी तरह बदल दिए हैं। इन बदले हालात में पीएम मोदी ने बिना वक्त गंवाए दक्षिण एशिया के देशों को एक मंच पर लाने में सफलता पाई। पाकिस्तान यहां भी ओछापन दिखाने से बाज नहीं आया, लेकिन मोदी ने अपना फोकस सिर्फ कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर बनाए रखा। उनकी पहल के तुरंत बाद अमेरिका और दूसरे देशों ने इसी तरह की पहल शुरू कर दी। जी–20 देशों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बारे में औपचारिक तौर पर कहा गया कि वह पीएम मोदी की पहल से प्रेरित होकर की गई है। इसके बाद यूरोपीय देश एक मंच पर आए। इसके बाद आती है बीमारी से निपटने के लिए संसाधनों के आदान–प्रदान की बात। भारत ने अमेरिका सहित कई जरूरतमंद देशों को पारासिटामोल, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन आदि दवाएं मानवीय आधार पर देने का फैसला किया। इसके लिए निर्यात पर लगी पाबंदियां भी कम कीं। इन तमाम कोशिशों और पहलकदमियों के मद्देनजर तमाम देशों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मोदी की सराहना की। पिछले दस दिनों के अंदर पीएम मोदी की विश्व के दो दर्जन राष्ट्र प्रमुखों से बात हो चुकी है। कोरोना संकट के दौरान ही दूसरे देशों में फंसे लोगों को सुरक्षित लाने का सअसे बड़ा ऑपरेशन भी भारत ने ही किया। और अगर अब तक सामने आए कोरोना के मामलों को देखें तो दूसरे देशों के मुकाबले भारत में हालात बेहतर ही लग रहे हैं।

अष्टयोग-5015

1	5		7		2	
	28		35		28	
7		2		3	1	5
	32		32		31	
6	3	1		2		
4	33		30	5	35	7
	2	7	4			3

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5014 का हल

2	1	3	7	6	5	4
1	22	7	38	5	41	3
3	4	1	2	7	6	5
7	32	6	30	3	35	2
6	3	2	5	4	1	7
4	32	5	30	2	24	1
5	3	4	7	1	2	6

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

अलग–अलग छात्र संगठन

मोहन। डीयू के वाइस चांसलर वही थे जो इमरजेंसी के वक्त भी थे। आरोप था कि उन्होंने इमर्जेंसी के दौरान प्रफेसरों और छात्रों को अरेस्ट करवाया था। स्वाभाविक रूप से छात्रों में उनके खिलाफ आक्रोश था। छात्रों ने विरोध शुरू किया और मांग की कि वाइस चांसलर को हटाया जाए, लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया। विरोध के दौरान ही एक दिन हिंसा भड़क गई और वाइस चांसलर के साथ भी मारपीट हुई। नतीजा यह हुआ कि विजय गोयल, रजत शर्मा सहित कुछ और लोगों को यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया। उस वक्त गोविंदाचार्य एबीवीपी का जिम्मा संभाल रहे थे। तब एबीवीपी ने फैसला किया कि अब संगठन पर फोकस करेंगे और छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह 1978 की बात है। इसके कुछ वक्त बाद ही छात्र संगठन का चुनाव होना था। सो जनता विद्यार्थी मोर्चा का गठन हुआ। डीयू छात्र संघ का चुनाव जनता विद्यार्थी मोर्चा ने लड़ा। यह जनता पार्टी का छात्र संगठन था। उसमें छात्र तो वही थे जो एबीवीपी में थे।